

भ्रष्टाचार मिटाने हेतु जनता की मदद चाहिये: लोकायुक्त

भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टाचारियों का पालन पोषण तो खुद मुख्यमंत्री एवं उनका मंत्री मंडल तथा विधायक मंडल करते हैं। उनकी आज्ञा एवं संरक्षण के बिना तो बड़े से बड़ा अफसर व छोटे से छोटा कर्मचारी एक पैसा भी रिश्वत नहीं ले सकता।

फरीदाबाद (म.मो.) जिले के सत्र न्यायाधीश और उसके बाद पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के जज रह चुकने के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कृपा से हरियाणा के लोकायुक्त बने प्रीतम पाल 14 मई को शहर में पधारे। उनके जिम्मे हरियाणा सरकार ने राज्य से भ्रष्टाचार समाप्त करने का काम लगाया है। इसी सिलसिले में वे जनता की मदद लेने यहाँ आये थे। भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता से ही इसे समाप्त करने हेतु मदद मांगना ठीक वैसा ही लगता है जैसे भूखों मर रहे लोगों से स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी रसोई को खाली करने हेतु मदद मांगना। सन् 2004 में यह पद सृजित किया गया था। इसके कार्यालय व स्टाफ आदि पर तो करोड़ों रूपए सरकार ने खर्च कर दिये लेकिन भ्रष्टाचार में कहीं कोई कमी नजर नहीं आती। पिछले 5 वर्ष इस पद पर मौजूद ले चुके एक सेवानिवृत्त जज सूद इस पद की पेंशन का ही मुकदमा सरकार से लड़ते फिर रहे हैं। दरअसल इस तरह के पद कोई भ्रष्टाचार खत्म करने के लिये नहीं बल्कि अपने उन चहत्तों को उपकृत



भ्रष्टाचार की नौकरी में प्रीतम पाल

करने हेतु बनाये जाते हैं जिन्होंने अपने सेवाकाल में सरकार को उपकृत किया होता है। भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टाचारियों का पालन पोषण तो खुद मुख्यमंत्री एवं उनका मंत्री मंडल तथा विधायक मंडल करते हैं। उनकी आज्ञा एवं संरक्षण के बिना तो बड़े से बड़ा अफसर छोटे से छोटा कर्मचारी एक पैसा भी रिश्वत नहीं ले सकता। सर्वविदित है कि योग्य

एवं ईमानदार लोगों की जगह नालायक एवं भ्रष्ट लोगों की भर्तियां एवं है। भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टाचारियों का पालन पोषण तो खुद मुख्यमंत्री एवं उनका मंत्री मंडल तथा विधायक मंडल करते हैं। उनकी आज्ञा एवं संरक्षण के बिना तो बड़े से बड़ा अफसर छोटे से छोटा कर्मचारी एक पैसा भी रिश्वत नहीं ले सकता। सर्वविदित है कि योग्य

कि योग्य एवं ईमानदार लोगों की जगह नालायक एवं भ्रष्ट लोगों की भर्तियां एवं नियुक्तियां इन्हीं राजनेताओं द्वारा की जाती है। यदि भूले भटके कोई योग्य एवं ईमानदार व्यक्ति कहीं नियुक्ति पा भी जाये तो उसे ये लोग काम नहीं करने देते। उसने यदि किसी भ्रष्टाचारी को पकड़ भी लिया तो ये नेता लोग उस भ्रष्टाचारी की ढाल बन कर खड़े हो जाते हैं। जिले भर के भ्रष्टाचारियों के बीच में बैठकर प्रीतमपाल द्वारा भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये जनता की मदद मांगना किसी नौटंकी से कम नहीं लग रहा था। इनता ही नहीं इस काम में मदद करने वाला व्यक्ति जो धक्के खायेगा, अपना समय बर्बाद करेगा वह अलग से एक हजार रूपए की फीस भी ड्राफ्ट द्वारा लोकायुक्त को देगा। इसके बावजूद यदि मदद करने वाला झूठा साबित हो गया तो उस पर दस हजार का जुर्माना व 3 साल की कैद भी हो सकती है। सर्वविदित है कि भ्रष्टाचार का मकड़जाल इतना मजबूत व इसे रोकने का कानून इतना लचर है कि भ्रष्टाचारियों का कुछ नहीं बिगड़ सकता। अब यह कोई

कैसे साबित कर सकता है कि उसने अपने भूखंड की सीएलयू कराने के लिए छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारियों एवं मुख्यमंत्री तक करोड़ों की रिश्वत दी है, परन्तु इस बात का पता सब को है, प्रीतमपाल को भी जरूर पता होगा। प्रीतमपाल जी किसी तहसील में बिना रिश्वत दिये कोई रजिस्ट्री या दाखिल खारिज ही चढवा कर दिखा दें, अथवा हूडा में किसी प्लाट का कम्पलीशन या ट्रांसफर या कोई भी छोटे से छोटा काम बिना रिश्वत के करा दें। कोई भी महकमा ऐसा नहीं बचा जहाँ खुले आम तयशुदा दरों पर रिश्वत न ली जाती हो और प्रीतमपाल जी इसे मिटाने का जिम्मा लिये फिर रहे हैं। दरअसल प्रीतमपाल भी खूब अच्छी तरह समझते हैं कि यह सब तो यूँ ही चलता आया है और यूँ ही चलता रहेगा। उन्हें इससे न कभी दिक्कत थी न होगी। उन्हें तो बस 5 साल की अतिरिक्त नौकरी से ही मतलब है।

ऑपरेशन ओसामा के दिन लाहौर से

लाहौर की सुबह थोड़ी देर से होती है क्योंकि रात देर तक सभी हंसते खलते खाते पीते रहते सुबह सवेरे भारत से फोन आया कि पाकिस्तान में क्या हाल है तो पता चला कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया है तो हम एक दम टी.वी. की ओर भागे परन्तु बिजली न होने की वजह से केबल बंद थी इन दिनों काफी अरसे से पाकिस्तानवासी बिजली की किल्लत से जूझ रहे हैं। खैर थोड़ी देर में वहाँ के सभी चैनलों पर चर्चाओं और समाचारों में ओसामा छाप हुए थे।

सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के आम आदमी पर ओसामा के मरने का कोई असर नहीं था। दफ्तरों सड़कों और बाजारों में रोजाना की तरह रोक थी और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे कहीं भी ओसामा की चर्चा नहीं थी। पुलिस कुछ सतर्क अवश्य हो गई थी। लेकिन कहीं कोई विरोध प्रदर्शन इत्यादि नहीं हुए। अगले दिन कुछ समाचार पत्रों में पढ़ा कि कुछ जगहों पर ओसामा की नमाजे जनाजा पढ़ी गई है तो पता चला कि ये कुछ एजेंसियों द्वारा प्रायोजित थीं और उनकी संख्या नगण्य थी। मसला ये कि आम आदमी को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं, वो तो अपनी रोजी रोटी में व्यस्त हैं।

दूसरी बात क्या सच में पाकिस्तान उग्रपंथियों और गैर कानूनी धंधा करने वालों को पनाह देता है? ओसामा के पाकिस्तान में होने से इस बात की पुष्टि तो होती है। मुद्दा ये है कि दो-तीन दिन तक तो स्वयं पाकिस्तान का शासक वर्ग सकते में था कि कहे तो क्या कहे। कि ओसामा एबटाबाद में उनकी जानकारी में रह रहा था या बिना जानकारी के। हालात को देखते हुए शायद ही कोई मूर्ख इस बात का भरोसा करे कि ओसामा उनकी जानकारी के



वे सच है कि पाकिस्तान और भारत की आम जनता एक दूसरे के खिलाफ नहीं है और आज भी बटवारे को दिल से कबूल नहीं करती हर आम पाकिस्तानी की ताहिश दिल्ली बम्बई और ताज महल देखने की है लेकिन ये दोनों तरफ के हुक्मरान क्यों रोकते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए क्यों वीजा देने से इतनी अडचने डालते हैं। अगर दोनों तरफ के लोगों को खुले से मिलने दिया जाए तो मेरा यकीन है कि बर्लिन की दीवार की तरह हमारी सरहदें भी टूट जायेंगी और दुनिया की कोई ताकत इस टूट को नहीं रोक पाएगी न मजहब न अमेरिका और न उग्रवादी अमेरिका के इस हमले से पाकिस्तान का शासक वर्ग गहरे सदमे में चला गया कि वो क्या कहे हमला उनकी जानकारी में हुआ है या नहीं।

बिना रह रहा था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिलेटरी एकेडमी से महज 500 गज की दूरी पर एक मकान, जिसकी 14 फुट की दीवारें हो उन पर 4 फुट तक काटिदार तार लगी हो, दरवाजे लगातार बंद रहते हों कोई खिड़की तक न नजर आती हो और खिड़कियों के सामने भी 7 फुट ऊंची दीवारें हो और वहाँ के वासियों का आम नागरिकों से कोई कोतुहल वास्ता न हो। वहाँ के दरवाजे कभी कभी कुछ गाड़ियों के लिए खुलते थे और बंद हो जाते थे। शुरु में तो पड़ोसियों के लिए कौतुहल का विषय था, परन्तु बाद में एबटाबाद जैसे सुस्त शहर ने इसे नजर अंदाज कर दिया। इस इमारत की ओर मिलट्री के खुफिया

विभाग की दृष्टि न गई हो इसे माना नहीं जा सकता।

तीसरी बात, क्या ये सच है कि पाकिस्तान में सेना एक समानान्तर सत्ता का केंद्र है और आईएसआई उसके अंतर्गत काम करती है और सरकार के नियंत्रण से बाहर है और इसका बर्ताव एक स्वशासी संस्था जैसा है। क्योंकि वहाँ के टी.वी.चैनलों पर जिस तरीके से सरकारी नुमाईदे बयान दे रहे थे, उससे उनकी शकल से बेचारागी टपक रही थी। वो अमेरिकी आर्मी और ओसामा के बारे में बड़ा बैलेंस बना कर बोल रहे थे क्योंकि जब कभी भी पाकिस्तानी नेता अमन और दोस्ती की बात करते हैं तो कहीं न कहीं ऐसी वारदात हो जाती है

कि रेल पटरी से उतर जाती है। ऐसे में यदि सरकार को नजर अंदाज करके सेना और आईएसआई उग्रपंथियों और अपराधियों को पनाह देती है या भारत में उग्रवादी घटनाओं को प्रायोजित करती है तो कोई हैरत की बात नहीं है।

ये सच है कि पाकिस्तान और भारत की आम जनता एक दूसरे के खिलाफ नहीं है और आज भी बटवारे को दिल से कबूल नहीं करती। हर आम पाकिस्तानी की इच्छा दिल्ली बम्बई और ताज महल देखने की है लेकिन ये दोनों तरफ के हुक्मरान क्यों रोकते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए क्यों वीजा देने में इतनी अडचने डालते हैं। अगर दोनों तरफ के लोगों को खुले से मिलने दिया जाए तो

—विनोद मलिक

मेरा यकीन है कि बर्लिन की दीवार की तरह हमारी सरहदें भी टूट जायेंगी और दुनिया की कोई ताकत इस टूट को नहीं रोक पाएगी, न मजहब न अमेरिका और न उग्रवादी। अमेरिका के इस हमले से पाकिस्तान का शासक वर्ग गहरे सदमे में चला गया कि वो क्या कहे हमला उनकी जानकारी में हुआ या नहीं। शुरु में तो कहा गया कि ये एक संयुक्त प्रयास था परन्तु सी.आई.ए. प्रमुख पैनोटा ने जब कहा कि यदि इसकी सूचना पाकिस्तान को देते तो ये ऑपरेशन फेल हो जाता क्योंकि ओसामा को इसकी खबर मिल जाती। इस के बाद तो प्रधानमंत्री गिलानी, सेना प्रमुख कयानी से लेकर इमरान खान तक संप्रभुता का रोना रोने लगे। इस बारे में पाकिस्तान के प्रमुख वामपंथी नेता डा. लाल खान ने डेली टाइम्स लाहौर में संप्रभुता की गलतफहमी दूर करने हेतु एक जोरदार लेख लिखा। जिसमें कहा गया है कि जो देश हर काम करने से पहले अमेरिका की परमिशन लेता हो और करने के बाद अमेरिका को सफाई देता हो उस देश की कैसी संप्रभुता होगी। इस घटना के तुरंत बाद आईएसआई प्रमुख शुजा पाशा सफाई देने अमेरिका पहुंच गए। इ धर पाकिस्तानी अखबारों में अमेरिका को धमकाने का काम शुरु हो गया। अब तो सीआईए ने कह दिया है कि जनरल मुशर्रफ से मुहायदा हो गया था कि अमेरिका को छूट है कि जब चाहे जहाँ चाहे बिना पूछे ओसामा को मार सकता है और उसे अमेरिका के खिलाफ बोलने की छूट भी रहेगी ऐसे में संप्रभुता का रोना एकदम बेकार की बात है।